

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

विविध अपील (Miscellaneous appeal) वाद सं० :-87/2023-24

रंथु साहु वगै०

बनाम

लखन साहु वगै०

25.07.24

1. अपीलार्थी रंथु साहु, पुनी साहु दोनों के पिता-भीम साहु, राजेन्द्र साहु, अनिल साहु, सुनिल साहु, रविन्द्र साहु चारों के पिता-देवलाल साहु सभी ग्राम-टिटिही थाना-कामडारा जिला-गुमला के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया के विविध अपील वाद सं०-07/2020-21 दिनांक-13.06.2023 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर रिवीजन दायर किया गया है।

अपीलार्थीगण के Miscellaneous appeal पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया।

2. अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-टिटिही थाना-कामडारा का खेवट सं०-2 से खाता सं०-16 एवं 18 बना है। प्रश्नगत भूमि खतियान में मझियस दर्ज है। अपीलार्थीगण जमीन्दार परिवार से आते हैं और मझियस भूमि जमीन्दार का विशेषाधिकार भूमि होता है। खेवट सं०-2 में दो खेवटदार थे जिसमें एक खेवटदार मदन साहु नावलद मृत हो गये। अपीलार्थी खोता साहु के वंशज एवं उत्तराधिकारी है।

3. खेवट सं०-02 में कुल 343.21 एकड़ भूमि है। निबंधित पट्टा सं०-651/1935 दिनांक-21.06.1935 वाले पट्टा में 1045.88 एकड़ भूमि को निबंधित कराया गया है जो कि एकदम गलत एवं संदेहास्पद है। उक्त पट्टा में खाता प्लॉट एवं रकबा दर्ज नहीं है। उत्तरवादी का यह कथन कि खेवट सं०-3 का भूमि को जोड़कर 1045.88 एकड़ भूमि निबंधित पट्टा से प्राप्त है, जो गलत है। उक्त निबंधित पट्टा में केवल खेवट सं०-2 अंकित है। खेवट सं०-03 का कही भी उक्त निबंधित पट्टा में उल्लेख नहीं है। उत्तरवादी का यह कथन गलत है कि सम्पूर्ण मौजा का जागीरदार को खेवट सं०-3 की भूमि को 12 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया था। खेवट सं०-03 में किसी भी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है तो किस जागीरदार को लीज पर 12 वर्षों के लिए दिया गया था।

4. प्रश्नगत भूमि का जागीरदार खोतो साहु थे तो उन्हें 12 वर्ष के लीज में लिए गए भूमि का मालिक नहीं थे, तो उनको भूमि बिक्री करने का कोई हक अधिकार नहीं था। निबंधित बिक्री पट्टा अपने आप में ही संदेहास्पद है। निबंधित पट्टा को आधार मान कर उत्तरवादीगण के द्वारा दाखिल खारिज करा लेना गलत एवं न्याय संगत नहीं है। उत्तरवादीगण का बिक्री पट्टा गलत है। कानून में यह प्रावधान है कि कोई बड़ा दस्तावेज जिससे की झगड़ा हो और उक्त दस्तावेज के द्वारा न्यायालय को धोखा देकर अपने पक्ष में आदेश करा लिया गया हो तो उक्त दस्तावेज को

कभी भी निरस्त किया जा सकता है। A.I.R 1994 (S.C) “Withholding of vital document relevant to Litigation- It is found on court-guilty party is liable to be thrown out at any stage”

5. प्रश्नगत भूति का हाल सर्वे में सर्वे अधिकारी प्रत्येक प्लॉट ओर सरजमीन में जाकर सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के उपरान्त अपीलार्थी के पूर्वज भीमा साहु का दखल कब्जा पाया। खेवट सं०-2 का आर० एस० खाता सं०-16 एवं 18 बना जिसका हाल सर्वे में खाता सं०-94 बना है, जिसमें कुल 36 प्लॉट है जिसका कुल रकबा-24.05 एकड़ भूमि है। प्रश्नगत भूमि पर भीमा साहु का दखल कब्जा है। उत्तरवादीगण का यह कथन गलत है कि भीमा साहु के नाम पर हाल सर्वे में खाता सं०-94 बन गया जिसका अपील उत्तरवादी के द्वारा सी०एन०टी०एक्ट की धारा 89 के तहत किया गया जिसका वाद सं०-11/1985 थी, जो पहले खारिज हो चुका है। उक्त वाद के खारिज होने के पश्चात अपीलार्थीगण के पूर्वज को बण्डा पर्चा को ही बहाल रखते हुए हाल सर्वे का खाता सं०-94 में अपीलार्थी के पिता-भीमा साहु के नाम पर नया खतियान फाईनल बना जिसमें 36 प्लॉट है तथा कुल रका-24.05 एकड़ है। J.L.J.R 2003(2) “If records if right is finally published, It shall be conclusive evidence that the record has been duly made according to Law”

6. उत्तरवादीगण का यह कथन कि बंटवारा वाद सं०-28/1956 दिनांक-02.04.1957 को हुआ एवं इजराय वाद सं०-31/1959 भोगला साहु के द्वारा किया गया। उक्त दोनों वादों में न तो अपीलार्थी को या अपीलार्थी के पिता को पार्टी बनाया गया था। दाखिल खारिज का आधार उत्तरवादी का 1935 का निबंधित बिक्री पट्टा है जिसमें सिर्फ खेवट सं०-2 दर्ज है और खेवट सं०-2 में कुल रकबा-343.21 एकड़ भूमि है, जबकि खेवट सं०-2 से निबंधित पट्टा में 1045.88 एकड़ भूमि कय किया गया है, जो गलत एवं न्यायोचित नहीं है।

अपीलार्थी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता बसिया द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा अपने दावे के समर्थन निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

1. खतियान की छाया प्रति।
2. भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया द्वारा पारित आदेश की छाया प्रति।
3. खेवट की छाया प्रति।
4. निबंधित पट्टा सं०-651/35 की छाया प्रति।
5. A.I.R 1994(S.C) page 853 to 855 की छाया प्रति।
6. J.L.J.R 2003(2) page 708 to 714 की छाया प्रति।

उत्तरवादी का पक्ष

7. उत्तरवादीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता बसिया के द्वारा विविध

वाद सं०-07/2021-22 दिनांक-13.06.2023 द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है। अंचल अधिकारी कामडारा के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थीगण के अपील को निरस्त किया गया। प्रश्नगत भूमि का खाता सं०-16 कुल रकबा-27.95 एकड़ एवं खाता सं०-18 कुल रकबा-19.55 एकड़ है, जो मौजा-टिटही थाना-कामडारा जिला-गुमला में अवस्थित है।

8. प्रश्नगत भूमि का खतियान अपील सर्वे में खोतो वैगरह के नाम पर मझियस मालिक के रूप में बना है। प्रश्नगत भूमि खेवट सं०-2 की भूमि थी, जिसे खेवटदार खोतो साहु व मदन साहु थे। मदन साहु खतियान बनने के तुरंत बाद नावलद मृत्यु हो गई। खेवट सं०-2 की सभी भूमि खोतो साहु के स्वामित्व की हो गई। वर्ष-1935 में खोतो साहु को रुपयों की सख्त आवश्यकता पड़ी और उसने खेवट सं०-2 की सभी भूमि कुल रकबा-1045.88 एकड़ भूमि धुमा साहु, रामु साहु, भोगला साहु एवं अंधु साहु को निबंधित पट्टा सं०-651/1935 दिनांक-21.06.1935 के द्वारा उचित प्रतिफल राशि-4600.00 (चार हजार छः सौ रुपये) मात्र लेकर हस्तांतरित कर दिया तथा दखल भी उन्हें दे दिया।
9. प्रश्नगत भूमि कय करने के पश्चात क्रेतागण धुमा साहु वगैरह अपनी कय की गई भूमि पर संयुक्त रूप से दखलदार हुए तथा जमीन्दार को मालगुजारी अदा करने लगे। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात भी सरकार द्वारा इन्हें रैयत मानते हुए प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी उनके नाम पर कायम की गई है। क्रेता भोगला साहु के वारिस भिखवा साहु व साधुचरण साहु व उनकी माता द्वारा प्रश्नगत भूमि सहित अन्य भूमि के बंटवारा हेतु अन्य तीन क्रेतागण के विरुद्ध बंटवारा वाद सं०-28/1956 दायर किया गया और वह बंटवारा वाद दिनांक-02.04.1957 के निर्णय व डिक्री द्वारा डिक्री किया गया और भोगला साहु के वारिसों के हिस्से की भूमि को अलग करते हुए फाइनल डिक्री भी पारित की गई जिसमें खाता सं०-16 व 18 की भूमि सम्मिलित है। दिनांक-31.01.1959 को फाइनल डिक्री बनाने के पश्चात इजराय वाद सं०-31/1959 में भोगला साहु के वारिसों को उनके हिस्से की जमीन पर न्यायालय की प्रक्रिया से दखल देहानी भी दिलाई गई जिसमें खाता सं०-16 रकबा-6.01 एकड़ भूमि वह खाता सं०-18 रकबा-2.37 एकड़ भूमि पर भी भोगला साहु के वारिसों को दखल देहानी दिलाई गई।
10. दखल देहानी के बाद भोगला साहु के वारिसों के नाम पर उनके हिस्से की भूमि का नामांतरण कर उनके नाम पर उसकी सरकारी माल गुजारी रसीद निर्गत किए जाने लगी और पूरे कार्यवाही में किसी के द्वारा कोई आपत्ति कभी भी नहीं की गई। हाल सर्वे में गलती से खाता सं०-16 व 18 की भूमि का प्रारंभिक ड्राफ्ट पब्लिकेशन/बण्डा पर्चा वर्तमान अपीलार्थीगण के पूर्वज भीमा साहु वगैरह के नाम पर बन गया था, जिसकी जानकारी होने पर उत्तरवादीगण द्वारा उक्त बण्डा पर्चा को धारा-89 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 के अन्तर्गत चुनौती दी गई जिसका वाद सं०-11/1985 था। उत्तरवादीगण के दखल कब्जा और सुसंगत दस्तावेजों के आलोक में सर्वे अधिकारियों के द्वारा भीमा साहु वगैरह का नाम हटाकर उत्तरवादीगण के नाम प्रविष्ट करने का आदेश पारित किया गया। उक्त वाद में आदेश पारित होने के पश्चात् उत्तरवादीगण के हिस्से की भूमि का बण्डा पर्चा भी तैयार हुआ और हाल सर्वे का अंतिम खतियान का प्रकाशन भी उनके नाम हुआ जिसका हाल सर्वे खाता सं०-92 एवं 93 हुआ है।
11. उक्त आदेश के विरुद्ध वर्तमान अपीलार्थीगण या उनके पूर्वजों द्वारा कोई अपील या रिवीजन दायर नहीं किया गया, इसलिए वह आदेश व खतियान उन पर पूर्ण रूप से बाध्यकारी है। अपीलार्थीगण के पूर्वजों द्वारा स्वयं सभी प्रश्नगत भूमि

उत्तरवादीगण के पूर्वजों धुमा साहु वगैरह को वर्ष-1935 में ही प्रश्नगत सभी भूमि निबंधित पट्टा द्वारा हस्तांतरित की जा चुकी है और उस पर उत्तरवादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही दखलकार है, तथा उनके नाम पर जमाबंदी भी जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात से ही चलती आ रही है। अपीलार्थीगण का उन भूमि पर किसी प्रकार कोई दावा नहीं बनता है।

12. अपीलार्थीगण के मेमो ऑफ अपील में यह कथन है कि खाता सं०-16 के कुछ भूमि का खतियान हाल सर्वे में अपीलार्थीगण के नाम पर बना है, परन्तु वह खतियान सन् 1935 ई० के निबंधित पट्टा को दरकिनार करते हुए बना है और उस खतियान के विरुद्ध संबंधित उत्तरवादीगण द्वारा धारा-87 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अन्तर्गत आपत्ति भी दाखिल की गई है जिसका वाद सं०-37/2017 (कामडारा) है, जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी(कैप कामडारा) के न्यायालय में लंबित है। प्रतिपादित विधि का सिद्धांत है कि खतियान टाइटल का दस्तावेज नहीं है और मात्र खतियान बनने से किसी का भूमि पर अधिकार नहीं हो जाता है। प्रश्नगत भूमि पर पूर्वजों का टाइटल था, परन्तु इस वाद में अपीलार्थीगण के पूर्वजों द्वारा वर्ष 1935 में ही प्रश्नगत भूमि हस्तांतरित की जा चंकी है। अंचल अधिकारी कामडारा एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन में अपीलार्थीगण का प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा नहीं पाया गया है। नामांतरण का आदेश केवल और केवल दखल के आधार पर ही पारित किया जा सकता है। अपीलार्थीगण का प्रश्नगत भूमि पर कोई हक व दखल नहीं है।

13. प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व व बाद से ही उत्तरवादीगण व उनके पूर्वजों के नाम पर चलती आ रही है और यह प्रतिपादित विधि का सिद्धांत है कि लम्बे समय से चलती आ रही जमाबंदी राजस्व न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं की जा सकती है। अपीलार्थीगण का यह कथन है कि खेवट सं०-2 में मात्र 343.21 एकड़ भूमि थी, परन्तु वर्ष-1935 के निबंधित पट्टा में 1045.88 एकड़ भूमि बिक्री की गई है, जो कि निबंधित बिक्रय पत्र के संदर्भ में संशय उत्पन्न करती है। उत्तरवादीगण का कथन है कि खेवट सं०-2 की 702.67 एकड़ भूमि खोतो साहु वगैरह द्वारा खीरोधर ओहदार वगैरह को जरपेशगी (बंधक) में दी गई थी, जिसका खेवट सं०-3 था। धुमा साहु वगैरह द्वारा उक्त भूमि की बंधक राशि का भुगतान खीरोधर ओहदार वगैरह को किया गया था, जिसका जिक्र निबंधित पट्टा में की गई है। निबंधित पट्टा में कुल 1048.88 एकड़ भूमि का वर्णन किया गया है।

उत्तरवादीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता बसिया द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील वाद को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

1. खेवट सं०-2 एवं 3 का छाया प्रति।
2. निबंधित पट्टा सं०-651/35 का छाया प्रति।
3. निबंधित पट्टा सं०-651/35 का हिन्दी अनुवाद की छाया प्रति।
4. जमीन्दार द्वारा दाखिल रिट्रन का छाया प्रति।
5. सरकारी मालगुजारी रसीद की छाया प्रति।
6. वाद सं०-11/1985 का आदेशफलक की छाया प्रति।

6. वाद सं०-11/1985 का आदेशफलक की छाया प्रति।
7. पार्टीशन सुट सं०-28/50 में पारित आदेश की छाया प्रति।
8. पार्टीशन सुट सं०-28/50 का अंतिम डीग्री का छाया प्रति।
9. ईजराई वाद सं०-31/1959 का दखलदेहानी का छाया प्रति।
10. हाल-सर्वे खतियान का खाता सं०-92 एवं 93 का छाया प्रति।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पक्ष तथा निम्न अपीलीय न्यायालय के अभिलेख के सम्यक अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में कोई ठोस तथ्यात्मक दलील प्रस्तुत नहीं कर पाए।

अतः निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथोचित मानते हुए अपीलार्थी के म्यूटेशन रिवीजन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति निम्न अपीलीय न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संबंधित अंचल अधिकारी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित


उप्राप्त,
गुमला


उप्राप्त,
गुमला